केवल विभागीय उपयोग हेतु

महेन्द्र रंगा
MAHENDRA RANGA
मुख्य आयुक्त
CHIEF COMMISSIONER

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
मुख्य आयुक्त कार्यालय
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
जयपुर

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER
CGST & CENTRAL EXCISE
Jaipur

12 मार्च, 2024
D.O. No. GCCO/TECH/MISC/440/2023

प्रिय साथियों

विषय: 'संवाद': मार्च, 2024

देश में परीक्षा का समय चल रहा है। आपमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। वे अपनी पाठ्यपुस्तकों और नोट्स को पढ़ने, रात में अध्ययन करने, पेंसिलें चबाकर सभी सूत्रों को याद करने की कोशिश करने में व्यस्त हैं। हमें उम्मीद है कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शांत रहना अच्छे प्रदर्शन की कुंजी है और उन्हें घबराना नहीं चाहिए। माता-पिता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस समय वे उन पर तनाव न डालें। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही यह हमारे लिए भी मूल्यांकन का समय है। यह हमारे लिए जायजा लेने और भविष्य के लिए योजना बनाने का समय है। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम सभी से अपना सर्वश्रेष्ठ देने की अपेक्षा की जाती है।

2. ज़ोन द्वारा संग्रहित राजस्व वर्ष में तीसरी बार और लगातार दूसरे माह 2000 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। फरवरी माह तक राजस्व की वृद्धि दर 8.84% है। रुपये 23300 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में फरवरी तक रुपये 20790 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। हमारे सबसे बड़े राजस्व प्रदाता मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लगभग रुपये 500 करोड़ कम राजस्व का भुगतान किया है। इसकी भरपाई संभव नहीं हो सकी है। तकनीकी खराबी के कारण लगभग रुपये 40 करोड़ का राजस्व भी कम बताया जा रहा है। यह माह चालू वित्तीय वर्ष के अंत का प्रतीक है। मैं अधिकारियों से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मार्च माह के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का आग्रह करता हूं।

3. कर अपवंचना की दृष्टि से विगत माह काफी घटनापूर्ण रहा। सीजीएसटी, जयपुर ने छूट वाली आपूर्ति के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के नियम 42 और 43 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्स न करने के तीन प्रमुख मामलों का पता लगाया है और मेसर्स राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर, से 3.11 करोड़ रुपये, मैसर्स दादरवाल रोड लाइन्स, शाहपुरा से 1.18 करोड़ रुपये और मैसर्स राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर से 1.99 करोड़ रुपये की वसूली की है। इसी तरह के मुद्दे पर, सीजीएसटी, उदयपुर ने मेसर्स श्री बयान मातेश्वरीलॉजिस्टिक्स, उदयपुर से 80 लाख रुपये की वसूली की है। मेसर्स सीमेंस गेमेसा रिन्यूएबल

एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के विरुद्ध एक अन्य मामले में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पर जीएसटी के कम भुगतान के संबंध में, सीजीएसटी, जयपुर ने करदाता से 6.53 करोड़ रुपये की वसूली की है। इसके अलावा, एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीजीएसटी, उदयपुर द्वारा मेसर्स सिक्योर मीटर्स लिमिटेड से रुपये 1.14 करोड़ की आईटीसी रिवर्स करवाई गई, जिसके द्वारा गैर-मौजूद फर्मों द्वारा बनाए गए दस्तावेजो के आधार पर अनुचित आईटीसी का लाभ उठाया गया था।

4. इनवॉइसिस जारी करने में देरी के कारण जीएसटी के विलंबित भुगतान पर रुपये 12.31 करोड़ के ब्याज का भुगतान न करने के लिए सीजीएसटी, जोधपुर ने मेसर्स दिनेश चंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। करदाता से अब तक ब्याज राशि रुपये 5 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। एक अन्य मामले में, आयुक्तालय ने सड़क और किफायती आवासो के निर्माण के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की आपूर्ति पर कर की दर में बदलाव के कारण मेसर्स द्वारका दास दोशी द्वारा रुपये 2.67 करोड़ के कम जीएसटी के भुगतान का पता लगाया है। करदाता से इस मामले में अब तक 95 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। सीजीएसटी, अलवर ने मैसर्स ट्रांस एसीएनआर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अलवर, जो एयर कंडीशनिंग यूनिट और कंप्रेसर की आपूर्ति कर रही है और दोनों के लिए अलग-अलग इनवॉइसिस बना रहा था और एयर कंडीशनिंग यूनिट के लिए 28% और कंप्रेसर के लिए 18% की अलग-अलग दर से जीएसटी चार्ज कर रहा था, जबकि उक्त दोनों की आपूर्ति मिश्रित आपूर्ति के अंतर्गत आती है, और पूरे लेनदेन पर 28% की दर से जीएसटी लागू है, से ब्याज और शास्ति के साथ रुपये 5.67 करोड़ जीएसटी की वसूली की है। आवासीय रियल एस्टेट परियोजना के पूरा होने या प्रथम अधिभोग की तारीख तक बिना बिके रहने के कारण आईटीसी को वापस न करने के एक अन्य मामले में सीजीएसटी, अलवर ने तीन करदाताओं- मेसर्स त्रेहन होम्स डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, अलवर, मैसर्स त्रेहन अपना घर प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी और मैसर्स ऑक्सीरिच रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड से रुपये 1.62 करोड़ की वसूली की है।

5. डीजीजीआई, जयपुर ने श्री पंकज अग्रवाल, दिल्ली के खिलाफ फर्जी फर्मों के निर्माण/संचालन और रुपये 215.67 करोड़ के फर्जी आईटीसी को पारित करने के लिए माल रहित इनवॉइसिस जारी करने के मामले का खुलासा किया। इस मामले में, अब तक कुल 33.39 करोड़ रुपये की आईटीसी फर्जी फर्मों के आईटीसी लेजर में ब्लॉक कर दी गई है और 137 बैंक खाते प्रोविजनल तौर पर अटैच किए गए हैं। इसके अलावा, माल रहित इनवॉइसिस के आधार पर फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने और कर देनदारी के निर्वहन के लिए इसका आंशिक उपयोग करने और माल के बिना इनवॉइसिस जारी करके शेष आईटीसी को पारित करने के मुद्दे पर, डीजीजीआई, जयपुर ने मैसर्स गोयल केमिकल्स, कोटा के खिलाफ रुपये 3.34 करोड़ का मामला दर्ज किया और अब तक रुपये 1.63 करोड़ की वसूली की है।

6. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आईएएस के नेतृत्व में राज्य जीएसटी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान मुफ्त वस्तुओं की ज़ब्ती से संबंधित अनुकरणीय कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार जीता है। हमें भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पूर्ण क्षमता से काम करना चाहिए।

7. फरवरी में, डीजी सिस्टम्स ने सीबीआईसी के सभी क्षेत्र संरचनाओं में डेस्कटॉप (एआईओ), लैपटॉप और टैबलेट की आपूर्ति, स्थापना और संचालन के लिए एवम विभिन्न LAN उपकरणों (स्विच, यूपीएस, रैक, वाईफाई, नोड्स आदि) के आकलन के लिए 800 सीबीआईसी स्थानों के साइट सर्वेक्षण, जिसे डीजी सिस्टम्स द्वारा एमपीएलएस कनेक्टिविटी पर काम करने या मेसर्स बीएसएनएल के साथ नए अनुबंध में इसके लिए प्रावधानित सीबीआईसी स्थानों पर मैप करने की आवश्यकता है, के लिये मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को क्रय आदेश जारी किये हैं। मेसर्स बीईएल द्वारा जल्द ही साइट सर्वेक्षण और उपकरणों की डिलीवरी शुरू करने की उम्मीद है। सभी आयुक्त इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों (सिस्टम मैनेजर/नोडल अधिकारी) को आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं।

8. एसीईएस-जीएसटी मॉड्यूल से जीएसटीएन बीओ में सुचारु परिवर्तन के लिए, नासिन, फरीदाबाद मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दे चुका है। नासिन, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 27.02.2024 को सभी प्रधान आयुक्तों/आयुक्तों के साथ परिवर्तन प्रक्रिया पर एक परस्पर सम्वाद सत्र भी आयोजित किया गया है। अब, नासिन, जयपुर के समन्वय से, इस जोन के मास्टर ट्रेनर्स मार्च और अप्रैल माह के दौरान 16 बैचों में इस जोन के शेष सभी अधिकारियो को प्रशिक्षण देंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इसे गंभीरता से लें और इन प्रशिक्षणों का भरपूर लाभ उठायें।

9. **'संवाद'** के इस संस्करण के लिखे जाने तक, 82 नए निरीक्षक, 1 कार्यकारी सहायक और 27 कर सहायकों ने जोन में कार्यभार ग्रहण किया है। उनमें से कुछ पहले ही इंडक्शन ट्रेनिंग में शामिल हो चुके हैं। बाकी के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होगा। मैं इन सभी अधिकारियो को विभाग में चयन पर बधाई देता हूं और जयपुर जोन में उनका स्वागत करता हूं।

10. इस माह के **'ज्ञान संग्रह'** में निम्नलिखित दो (02) लेख सम्मिलित किये जा रहे हैं। मैं लेखकों का आभारी हूं जिन्होंने अपना उपयोगी अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए समय निकाला।

(ए) *क्या सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत जारी कारण बताओ ज्ञापन में प्रस्तावित मांग पर अधिनियम की धारा 73 के तहत फैसला सुनाया जा सकता है* – लेखक: श्री सुनील कुमार वर्मा, अधीक्षक, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अलवर; और,

(बी) *सुनने की कला* - लेखक: श्री अरविंद सिंह, अपर सहायक निदेशक, सीओई, नासिन, फ़रीदाबाद।

11. हम अपने तीन अधिकारियों अर्थात् श्री विजय सिंह मीना, संयुक्त आयुक्त, श्री मुखलेश जैन, निरीक्षक और श्री प्रताप सिंह सिसौदिया, निरीक्षक को विदाई देते हैं, जो फरवरी, 2024 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री तरूण कांत, श्री शिव कुमार गुप्ता, श्री संजीव सिंह रावत, श्री अवतार सिंह लबाना और श्री विनय अवस्थी ने भी फरवरी के दौरान सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। सभी को उनके भावी जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं।

12. वर्ष का सबसे अच्छा मौसम चल रहा है। यह इसका आनंद लेने का समय है। विदा लेने से पहले, मैं आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएँ भी देना चाहता हूँ। सफलता के रंग से अधिक चमकीला कोई भी रंग नहीं है। हम इस रंग को अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को समर्पित

करते हैं, जिन्होंने कर्तव्य के प्रति समर्पण के साथ कड़ी मेहनत की है। इस अवसर पर महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन की निम्नलिखित पंक्तियाँ हमारे लिए मार्गदर्शक प्रतीत होती हैं:-

प्रेम चिरंतन मूल जगत का, वैर-घृणा भूलें क्षण की,
भूल-चूक लेनी-देनी में सदा सफलता जीवन की,
जो हो गया बिराना उसको फिर अपना कर लो।
होली है तो आज शत्रु को बाहों में भर लो!

अगले माह तक,

भवदीय,

(महेंद्र रंगा)

सेवा में:- टीम जयपुर जोन।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

(i) ओएसडी, अध्यक्ष, सीबीआईसी, नई दिल्ली।
(ii) निजी सचिव, सदस्य (जीएसटी/सीई/एसटी एवं क्षेत्रीय प्रभारी), सीबीआईसी, नई दिल्ली।
(iii) मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर
(iv) प्रधान एडीजी, नासिन/डीजीजीआई, जयपुर

ज्ञान संग्रह

मार्च, 2024

GYAN SANGRAH

MARCH, 2024

Whether the demand proposed in SCN issued under Section 74 of the CGST Act, 2017 can be adjudicated and confirmed by the Adjudicating Authority under Section 73 of the Act

By – Sunil Kumar Verma, Superintendent,
CGST & CX, Alwar

As per Section 75(2) (2) of the CGST Act, 2017, where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or *court* concludes that the notice issued under sub-section (1) of section 74 is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73. Similar provisions are also available in the Central Excise Act, 1944, the Finance Act 1994 and the Customs Act, 1962.

2. Before going in to the issue it appears essential to look into some of the definitions under CGST Act, 2017

> ***2(4) "adjudicating authority"*** *means any authority, appointed or authorised to pass any order or decision under this Act, but does not include the [Central Board of Indirect Taxes and Customs], the Revisional Authority, the Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority for Advance Ruling, [The National Appellate Authority for Advance Ruling] [the Appellate Authority, the Appellate Tribunal and the Authority referred to in sub-section (2) of section 171];*
>
> ***2(8) "Appellate Authority****" means an authority appointed or authorised to hear appeals as referred to in section 107;*
>
> ***2(9) "Appellate Tribunal"*** *means the Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under section 109;*

The expression **'Court'** is not defined in the CPC (Civil Procedure Code, 1908) nor in the General Clauses Act, 1897 however as per the Indian Evidence Act 1872 "*Court" includes all Judges and Magistrates and all persons, except arbitrators, legally authorised to take evidence.*

Further, limited meaning of the term "court" has been provided in Para 2 of SCHEDULE III of the CGST, Act,2017 according to which term ***"court " includes District Court, High Court and Supreme Court.***

3. There are separate and exclusive provisions to issue notice, determine the tax and issue the order where reason of fraud, or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax is found as well as cases other than **the reason of**

fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax as discussed below:- .

(i) Where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, **other than** ***the reason of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax,*** proper officer shall serve notice under Section 73(1) on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder. The notice under Section 73(1) is to be issued at least three months prior to the time limit specified in sub-section (10) for issuance of order i.e. within three years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within three years from the date of erroneous refund.

(ii) Where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised **by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax**, a notice is to be served on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause under Section 74(1) of the CGST Act, 2017 as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to the tax specified in the notice. The notice under Section 74(1) is to be issued at least six months prior to the time limit specified in sub-section (10) for issuance of order i.e. within a period of five years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within five years from the date of erroneous refund.

4. In the Customs Act, 1962, the adjudicating Authority is permitted or authorized by the virtue of sub section (10B) of Section 28 if *the charges of collusion or any willful mis-statement or suppression of facts to evade duty has not been established then to decide within normal period.* ***However, i*****n the provisions related to Central Excise Act, Service Tax as well as CGST no such power or authority similar to** ***Appellate***

Authority **or *Appellate Tribunal* or *court has been* provided to the Adjudicating Authority. T**herefore, the adjudicating Authority under Central Excise Act, Service Tax or CGST is **not permitted / empowered or authorised to decide the cases within normal period if extended period and charges of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax is not established.**

4.1 This view can be conformed from combined comparison of the provisions reproduced in following table:

Section 75 (2) of CGST Act, 2017	**Section 11 A(9) of Central Excise Act, 1944**	**Section 73 (2A) of Finance Act, 1994**	***28(10B) of* Customs Act, 1962**
*Where any **<u>Appellate Authority or Appellate Tribunal or court</u> concludes** that the notice issued under sub-section (1) of section 74 is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73.*	*Where any* **appellate authority or tribunal or court concludes** ***that*** *the notice issued under sub-section (4) is not sustainable for the reason that the charges of fraud or collusion or any wilful misstatement or suppression of facts or contravention of any of the provisions of this Act or of the rules made thereunder with intent to evade payment of duty has not been established against the person to whom the notice was issued, the Central Excise Officer shall determine the duty of excise payable by such person for the period of 5 [two years], deeming as if the notice were issued under clause (a) of sub-section (1).*	*Where **any <u>appellate authority or tribunal or court</u> concludes** that the notice issued under the proviso to sub-section (1) is not sustainable for the reason that the charge of, –* *(a) fraud; or* *(b) collusion; or* *(c) wilful misstatement; or* *(d) suppression of facts; or* *(e) contravention of any of the provisions of this Chapter or therules made thereunder with intent to evade payment of service tax,* *has not been established against the person chargeable with the service tax, to whom the notice was issued, the Central Excise Officer shall determine the service tax payable by such person for the period of thirty months, as if the notice was issued for the offences for which limitation of thirty months applies under sub-section (1).*	*A notice issued under sub-section (4) shall be deemed to have been issued under sub-section (1), if such notice demanding duty is held not sustainable **<u>in any proceeding under this Act, including at any stage of appeal,</u>** for the reason that the charges of collusion or any wilful mis-statement or suppression of facts to evade duty has not been established against the person to whom such notice was issued and the amount of duty and the interest thereon shall be computed accordingly.]*

5. From the plain reading of provisions of Section 75 (2) of CGST Act, 2017 it is crystal clear that only Appellate Authority or Appellate Tribunal or court may order or conclude incase the charges of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax is not established then proper officer shall determine the tax payable deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73 of CGST Act. Similar power has been vested by the legislature to Appellate Authority or Appellate Tribunal or court in the matter related to Central Excise, Service tax as well as Customs.

6. In view of above, and for purpose of uniformity, removal of doubts (if any) as well as to safe guard the revenue where charges of fraud or any willful-misstatement or suppression of facts to evade tax is not established, adjudicating authority under CGST ACT may be vested power or author identical to Section 28 (10B) of Customs Act 1962 by amending Section 75(2) of CGST Act, 2017 and corresponding provisions of SGST or UT GST Act and or issuing clarification by the CBIC.

<u>Note</u>:

(i) *The above views or opinions expressed in the content do not necessarily reflect those of the individual, Department or Government and it is not intended to be used for legal advice or professional advice.*

(ii) *Thanks to Shri Umesh Kumar Agarwal, Superintendent for his support in preparation of this article.*

****

ART OF LISTENING

By – Arvind Singh, Additional Assistant Director,
Centre of Excellence, NACIN, New Delhi

Listening is the single most crucial skill in communicating and building your business, it increases productivity, boosts confidence and reduces errors. Listening can have numerous benefits, including making you popular, building your personal brand and expanding your relationship network. The importance of listening has been emphasised since ancient times. The Greek philosopher Diogenes once said,

"We have two ears and one tongue so to listen more and talk less"

In fact, researchers estimate that we only remember 25–50% of what we hear. So, why is listening in danger of extinction? According to Seth Horowitz, an auditory neuroscientist from Brown University,

"Listening is a skill we're in danger of losing in a world of digital distractions and information overload."

Why be a good listener

Listening is the gateway to learning. It opens up new avenues of growth and knowledge. The lesson gained through careful listening is sticky and long-lasting. People who listen well are liked and admired. It's easier and more fruit to talk to such people. Because they listen well, they give you better advice and solution. These are the people you can count on. These are the people you can look for valuable advice. Listening makes you calm and considerate.

Listening versus hearing

In order to get the most out of the information we are presented with, we have to make sure we are always listening and not just hearing. So, what is the difference between listening and hearing? There are many differences.

Listening is something altogether different from hearing, an unintentional (or possibly intentional) experience of one of your senses at work. What we hear may or may not become a part of us over time. Yet, what we truly listen to soaks into us at that very moment. Hearing is the act of perceiving and receiving sound; it's the use of one of your senses. Listening, on the other hand, is the act of hearing a sound and understanding what you hear. Hearing is easy. You just cannot control what your ears catch. Listening is harder. When you are listening, you are consciously choosing what you want to hear. Listening is a choice. Listening requires the willingness to focus and the act of providing your full attention. Listening requires engagement

and may require follow-up questions for full clarity and visibility. Listening is an art, requiring practice, skill, spirit, and inspiration.

Are you listening?

- You probably aren't listening if you are multi-tasking — texting, checking emails, listening to music and reading.
- You probably aren't listening if you can only remember the main idea but cannot remember details of the conversation.
- You probably aren't listening if all of your responses are neutral. If you do have questions or feedback, you are more likely to remember the conversation as it relates to you.
- You probably aren't listening if you leave the conversation with the same information you started with.

How to improve skill of listening?

There are a few simple things that you can do to improve your skill of listening.
1. Pay attention- Be attentive, but relaxed, face the speaker, maintain eye contact and listen to the words and try to picture what the speaker is saying.
2. Use Non-verbal cues- Pay attention to what isn't said—to nonverbal cues.
3. Keep the conversation alive- Ask questions only to ensure understanding.
4. Keep the speaker on track- Give the speaker regular feedback but wait for the speaker to pause to ask clarifying questions.
5. Avoid judgement- Keep an open mind.
6. Don't interrupt and don't impose your "solutions."

****